International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 02(II), April- June, 2025, pp. 135-142

जाति, वर्ग और पहुँचः ग्रामीण भारत में शैक्षणिक असमानता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पुष्पा मीणा*

सह–आचार्या, समाजशास्त्र, एस.आर.पी. राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान।

*Corresponding Author: pushpameena10278@gmail.com

सार

शिक्षा को एक प्रमुख उपकरण माना जाता है कि वह समाजिक परिवर्तन और समावेशन को बढ़ावा देती है, लेकिन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जाति, वर्ग और सामाजिक पहुँच जैसे संरचनात्मक कारक शिक्षा तक पहुँच को व्यापक असमानता पैदा करते हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र शैक्षणिक असमानता की समाजशास्त्रीय समझ विकसित करने का प्रयत्न करता है, विशेषरूप से इस संदर्भ में कि जाति और वर्ग आधारित संरचनाएँ शिक्षा तक पहुँच को कैसे नियंत्रित और सीमित करती हैं। भारत के ग्रामीण समाज में जातिगत पदानुक्रम न केवल सामाजिक सम्मान और संसाधन उपलब्धता को निर्धारित करता है, तथा यह शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुँचने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने एवं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, आर्थिक वर्गभेद, जैसे भूमिहीनता, निम्न आय स्तर एवं आजीविका की अनिश्चितता, बच्चों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखने में सहायक कारक बनते हैं। इस अध्ययन को गुणात्मक पद्धति के तौर पर किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों से केस स्टडी, गहन साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन के द्वारा डाटा संकलित किया गया है। अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक संरचनाएं, जैसे जातिगत भेदभाव, वर्ग आधारित संसाधन असमानता, और भौगोलिक दूरी, शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच और सततता को गहराई से प्रभावित करती हैं। विद्यालयों की अवस्थिति, अध्यापकों की अनुपलब्धता, भाषा की बाधा और सामाजिक बहिष्करण जैसे पहलू ग्रामीण शिक्षा की विफलता में योगदान करते हैं। इस शोध का उद्देश्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि यह भी दिखाना है कि इन असमानताओं को किस प्रकार सामाजिक नीति, संस्थागत पुनर्गठन और समुदाय आधारित पहलों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि शिक्षा को वास्तव में समान अवसरों का माध्यम बनाना है, तो केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सामाजिक चेतना, समावेशी नीति निर्माण और संरचनात्मक बदलावों की भी आवश्यकता है।

शब्दकोशः *जातिए वर्गए शैक्षणिक असमानताए ग्रामीणभारतए सामाजिक पहुँचए समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक बहिष्करण।*

प्रस्तावना

भारत के जैसे विविधतापूर्ण समाज में शिक्षा को सामाजिक समानता और आर्थिक विकास का आधार समझा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21। के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य कियागया है।

लेकिन, देश के ग्रामीण भागों में अभी भी शिक्षा तक पहुंच असमान और सीमित रही हुई है। यह असमानता आर्थिक नहीं है, बल्कि जाति, वर्ग और सामाजिक संरचना के कारण और भी जटिल हो जाती है।

भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित है, जो एकनिष्ठ रूप से आज भी ग्रामीण समाज में प्रभावी है। जातिगत वर्गीकरण पदानुक्रम शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं। सामाजिक भेदभाव, स्कूल में भौतिक संसाधनों की तथ्सेला, शिक्षकों की अनुपलब्धता, स्कूल तक दूरी, और पारिवारिक आर्थिक संकट कृ ये सभी कारक संयुक्त रूप से शिक्षा को एक विशेष वर्ग के लिए ही उपलब्ध बनाते हैं।

ग्रामीण इलाकों में न केवल आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी की भी कमी होती है। जहाँ तक मामला है, मुश्किल ही है कि स्कूल खोल दिया जाए या योजनाएँ तैयार दी जाएँ। जब तक समाज में गहराई से व्याप्त भेदभाव और सामाजिक दूरी को समझा नहीं जाएगा, तब तक समता लाना शिक्षा में मुश्किल होगा।

यह शोध इन सभी पहलुओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य है यह समझना कि किस प्रकार जाति, वर्ग और सामाजिक पहुँच ग्रामीण भारत में शिक्षा को प्रभावित करती है, और क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे यह असमानता समाप्त हो सके।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

शिक्षा को भारत में सशक्तिकरण का साधन माना जाता है, और यह लोकतांत्रिक समाज की आधार है। ग्रामीण भारत के वास्तविकता के संदर्भ में जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ शिक्षा समस्त जनों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाई है। वर्ष 2009 में निर्मित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे समुदाय आज भी शैक्षणिक दृष्टि से वंचित हैं।

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों (जैसे ASER रिपोर्ट्स) से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हैं – सामाजिक भेदभाव, आर्थिक मजबूरी, स्कूल की भौगोलिक दूरी, विद्यालय में सुविधाओं की कमी और सामुदायिकसहयोग की अनुपस्थिति।

जातिगत भेदभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गहराई से व्याप्त है। बहुत से मामलों में वंचित जातियों के बच्चों को विद्यालय में भेदभाव का सामना करना पड़ता है – जैसे अलग बैठाना, टीचर द्वारा उपेक्षा करना, या उनकी उपलब्धियों को नकारना। ये अनुभव न केवल बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्कूल में टिके रहने की संभावना को भी कम करते हैं।

इस पृष्ठभूमि पर यह शोध बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे यह समझा जा सके कि किस तरीके से शिक्षा सामाजिक संरचनाओं और धाराओं से प्रभावित होती है, और क्या किया जा सकता है जिससे समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

- ग्रामीण भारत में शैक्षणिक असमानता के प्रमुख सामाजिक कारणों की पहचान करना।
- जाति और वर्ग के आधार पर शिक्षा तक पहुँच में आने वाले अंतर को विश्लेषण करना।
- सामाजिक पहुँच और संसाधनों की उपलब्धता में असंतुलन का मूल्यांकन करना।
- शिक्षा व्यवस्था में फैले हुए सामाजिक भेदभाव और बहिष्करणके रूप को समझना।
- शिक्षा में समावेशी नीतियों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की सीमाएँ

- यह अध्ययन ग्रामीण भारत के ही एक समर्पित अध्ययन है।
- अध्ययन का फोकस जाति, वर्ग और सामाजिक पहुँच तक ही सीमित है।
- यह शोध अधिकांशतः गुणात्मकपद्धति पर आधारित है।
- शहरी क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं कियागया है।
- केवल प्राथमिक और माध्यमिकशिक्षा पर बिन्दुयबल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
- संस्थागत नीतियों की समीक्षा सीमित स्तर पर की गई है।

अध्ययन का महत्त्व

- यह अध्ययन ग्रामीण भारत में शैक्षणिक असमानता के सामाजिक आधारों को उजागर करता है।
- शोध समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से शिक्षा में व्याप्त भेदभाव और बहिष्करण को समझने में सहायता करता है।
- यह नीति निर्माताओं को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण हेतु दिशा प्रदान करता है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, और वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधी वास्तविक समस्याओं की पड़ताल करता है।
- यह शोध सामाजिक समरसता और समान अवसरों के स्थापना के लिए जरूरीप्रमाण प्रस्तुत करता है।
- यह अध्ययन समाज में प्रचलित ढांचागत भेदभाव को उजागर करके जागरूकता फैलाने में मददगार है।
- समुदाय आधारित शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के लिए यह गाइड का कार्य कर सकता है।
- शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ग्रामीण संदर्भ में शिक्षा सुधार के लिए ठोस सुझाव प्रदान करता है।

समीक्षा साहित्य

डॉ. सुप्रिया सिंह (2024)ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं के उभरते स्वरूप और प्रकृति लखनऊ विश्वविद्यालय की इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के दो ग्रामीण ब्लॉकों में जाति, वर्ग, भूमि–वितरण और सामाजिक पहचान की संरचनाओं से शिक्षा तक पहुँच पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दिखाता है कि कैसे शक्ति संरचना स्थानीय संस्थाओं (जैसे पंचायत, स्कूल) में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती है, जिससे पिछड़े वर्ग के बच्चों को उचित अवसर नहीं मिलते।

रामप्रसाद बैरवा (2024) शिक्षा एवं सामाजिक समानताः समाजशास्त्रीय विश्लेषण (ध्श्रप्त्ब्ज, दि० दिसंबर 2024) यह लेख शिक्षा को केवल साक्षरता से ऊपर उठकर समाज परिवर्तन और न्याय का साधन मानता है। इतिहास और वर्तमान दोनों को मिलाकर जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताओं की विवेचना की गई है। यह समाजशास्त्रीय दृष्टि से सुधार हेतु ठोस सुझाव प्रदान करता है।

नवीन कुमार मोक्टा व सुकांत महापात्र (2024) अनुसूचित जनजाति शिक्षा में समानता एवं समावेशनइस शोध में बतायागया है कि NEP-2020 के बावजूद जनजातीय छात्रों के लिए नामांकन अनुपात और ड्रॉप–आउट दर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। पाठ्यचर्या और सांस्कृतिक असंगतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।

स्वीटी सुप्रिया (NewsClick हिंदी, 2024)एससीध्एसटी क्रीमी-लेयरः उच्च शिक्षा में भारी असमानतान्ळ८ डेटा के आधार पर स्पष्ट कियागया है कि साथ ही क्रीमी-लेयर की व्याख्या और आरक्षण नीति की सीमाओं को रेखांकित कियागया है

आनंद कुमार व सोहम साहू (IIMB & IIMB–Loughborough, बंगालुरु, 11 जनवरी 2024) भारत में विज्ञान शिक्षा में जाति एवं लिंग की भूमिका विशेषकर उच्च माध्यमिक स्तर पर STEM प्रशिक्षण के चयन में जाति–लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को उजागर किया गया है। यह शोध दर्शाता है कि सामाजिक–आर्थिक कमजोर वर्गों के विद्यार्थी STEM में कम नामांकन करते हैं।

Ideas ForIndia (पुरा ब्लॉग, 2024)ग्रामीण भारत में स्कूल चयनः धारणा बनाम वास्तविकता माता–पिता की अंग्रेजी–माध्यम की धारणा और स्कूलों में वास्तविक भाषा परिवर्तन की असंगतियों को संख्यात्मक तौर पर दिखायागयाहै। यह शहरी–ग्रामीणशिक्षा अंतरों को भी उजागर करता है।

टार्गेटनोट्स (TargetNotes, 2025) शैक्षिक पद्धति में शैक्षिक अवसरों की असमानता एवं चुनौतिया ँयह दस्तावेज संविधान के अनुच्छेद 45 एवं 46 पर आधारित है और ग्रामीण व शहरी, जातिगत और लिंग–आधारित असमानताओं को सैद्धांतिक और संरचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करता है।

Drishti IAS (डेली न्यूज, फरवरी 2025) शिक्षा में अधिवास–आधारित आरक्षण के गुण और दोष यह समीक्षा नीति विश्लेषण के दृष्टिकोण से आरक्षण के सामाजिक लाभ और एकीकृत शिक्षा वातावरण पर संभावित प्रभावों की चर्चा करती है।

NyayTak (न्याय तक, 2024)सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रही है शैक्षिक ढांचे की विषमतायहलेख 21 राज्यों में 6–16 आयु वर्ग के ग्रामीण छात्रों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट का उपयोग करता है। इसमें शिक्षकों की अनुपस्थिति, डिजिटल उपयोग, पैसा उपलब्धता जैसी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत है।

Sangita Das (जुलाई 2023) शहरी-ग्रामीण शिक्षागत असमानता का तुलनात्मक विश्लेषण 15 राज्यों के डेटा विश्लेषण (1981–2011) पर आधारित यह शोध दिखाता है कि साक्षरता अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। माताओं की शिक्षा, विवाह आयु एवं महिला श्रम भागीदारी में सुधार से असमानता घट सकती

शोध पद्धति

इस शोध में गुणात्मक शोध पद्धति (Qualitative Research Methodology) का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विश्लेषण किया गया है कि ग्रामीण भारत में किस प्रकार जाति, वर्ग और सामाजिक पहुँच शैक्षणिक समानता को प्रभावित करते हैं। इस शोध में केस स्टडी, गहन साक्षात्कार (In&depth Interviews), प्रत्यक्ष निरीक्षण और फोकस समूह चर्चा (FGD) का उपयोग किया गया।

शोध क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुल छह गाँवों को चुना गया, जहाँ विभिन्न जातीय और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग निवास करते हैं।

नमूना आकार

- कुल प्रतिभागीः 80
- विद्यार्थीः 40 (SC, ST, OBC एवं सामान्य वर्ग से)
- अभिभावकः 20
- शिक्षकः 10
- पंचायत प्रतिनिधिः 5
- सामाजिक कार्यकर्ताध्स्वयंसेवीः 5

आंकड़ा विश्लेषण

प्राप्त आंकड़ों को विषयवस्तु–विश्लेषण (Content Analysis) की पद्धति द्वाराप्रयोग करके उनका विश्लेषण किया गया है। उत्तरों को जाति, आर्थिक वर्ग, लिंग, विद्यालयीय संरचना, सामाजिक अनुभव, शिक्षा तक

पहुँच आदि के विषय पर वर्गीकृत कर विश्लेषित कियागया है। आंकड़े की प्रस्तुति तालिकाओं के द्वारा की गई है, जिनकी व्याख्या नीचे दी गई है।

तालिकाएँ एवं व्याख्या

तालिका 1: जाति आधारित उपस्थिति एवं ड्रॉपआउट दर

जाति वर्ग	नामांकन (संख्या)	नियमित उपस्थिति	ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण
अनुसूचित जाति	15	8	भेदभाव, मजदूरी, संसाधनों की कमी
अन्य पिछड़ा वर्ग	15	12	पारिवारिक जिम्मेदारी
सामान्य वर्ग	10	10	अपेक्षाकृत बेहतर संसाधन

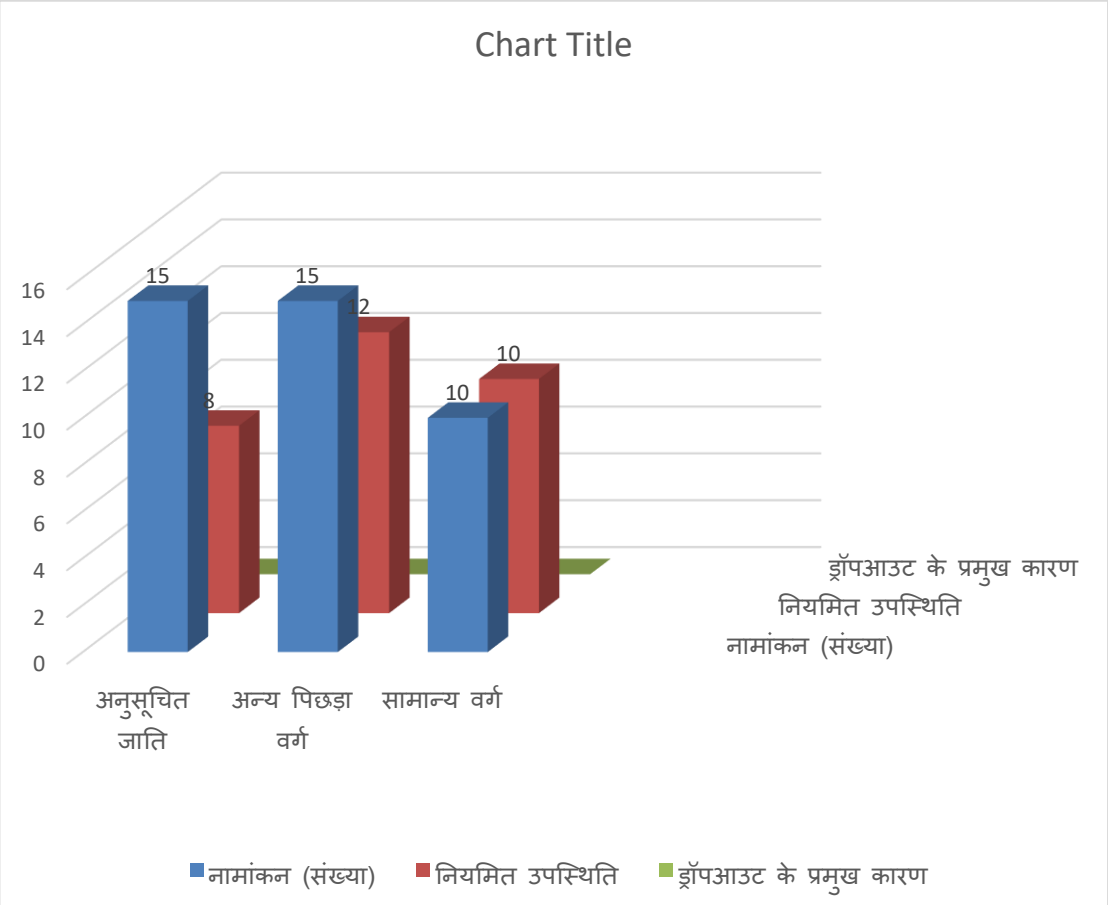

व्याख्याः अनुसूचित जातियों के छात्रों की उपस्थिति कम है, और उन्हें सामाजिक भेदभाव व आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है।

तालिका 2: आर्थिक वर्ग और विद्यालय का प्रकार

वार्षिक आय (₹)	बच्चों की संख्या	सरकारी विद्यालय	निजी विद्यालय
₹ 50,000 से कम	30	28	2
₹ 50,000 ₹ 1,00,000	30	20	10
₹1,00,000 से अधिक	20	8	12

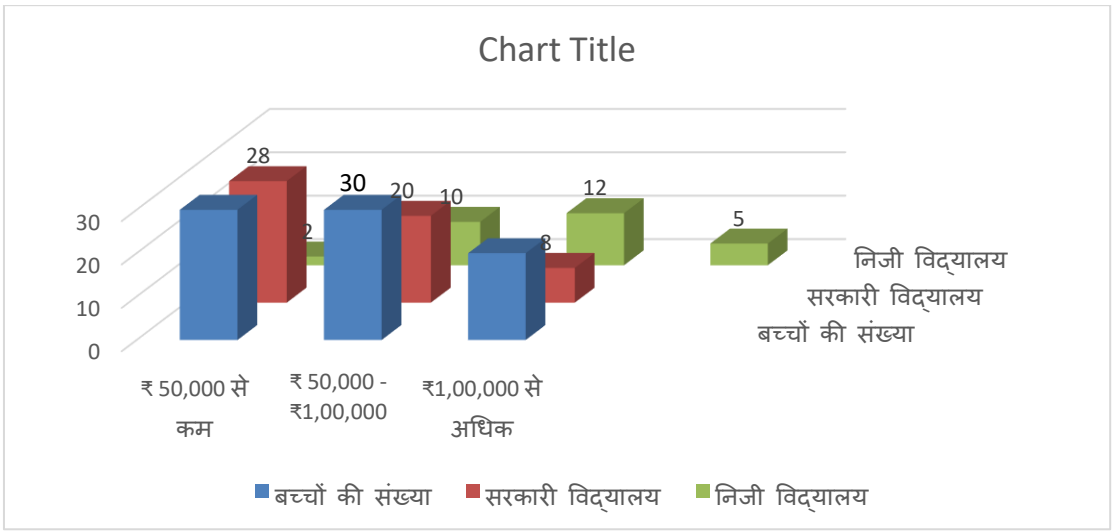

व्याख्या: निम्न–आय वर्ग के अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जहाँ संसाधनों की भारी कमी है।

तालिका 3: लिंग आधारित शैक्षणिक पहुँच

जातिवर्ग	लड़के (संख्या)	लड़कियाँ (संख्या)	मुख्यअंतर
अनुसूचित जाति	9	6	सुरक्षा, विवाहआदि
अन्यपिछड़ावर्ग	10	10	समान
सामान्यवर्ग	8	8	समान

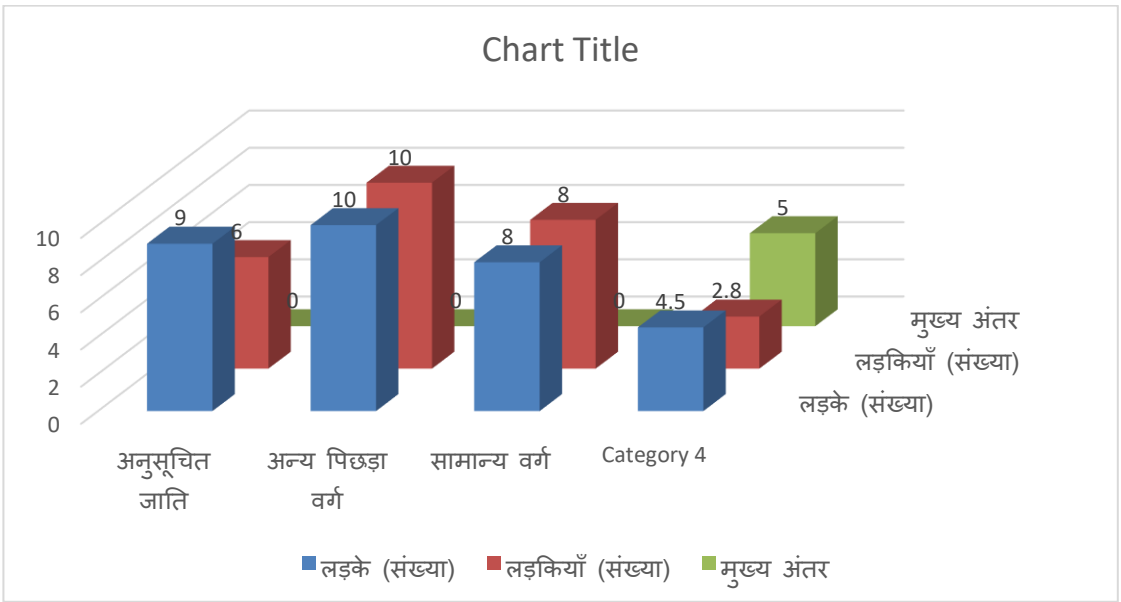

व्याख्या: अनुसूचित जातियों में लड़कियों की पढ़ाई में रुकावटें अधिक हैं, जैसे प्रारंभिक विवाह, घर का काम, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।

निष्कर्ष

- जातिगत पहचान जातकों की शैक्षिक अवसरों तक पहुँच को प्रभावित करती है।
- बच्चों की विद्यालय–चयन और निरंतरता आर्थिक वर्ग निर्धारण भी प्रभावित करता है।
- सरकारी विद्यालयों का स्थान अपेक्षाकृत खराब है जिससे कमजोर वर्ग के बच्चे पिछड़ते हैं।
- सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से लड़कियों को शिक्षा में अधिक अवरोध झेलने पड़ते हैं।
- योजनाएँ मध्याह्नभोजन योजना, पोशाक सहायता आदि प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन यह दिखाता है कि ग्रामीण भारत में शैक्षणिक असमानता एक गहरे और जटिल सामाजिक ढाँचे में निहित है। जाति, वर्ग और लिंग आदि सामाजिक घटक शिक्षा तक पहुँच को सीधे प्रभावित करते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों का शैक्षणिक प्रणाली में, संसाधनों की कमी, और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में सुधार लाने हेतु केवल नीतिगत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, अपर instead of और का अतिरिक्त उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक चेतना और समुदाय आधारित हस्तक्षेप भी आवश्यक हैं।

शोध से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति और आय वर्ग के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन और वातावरण प्राप्त होता है, जबकि निम्न वर्गों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को विशेष रूप से लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा की चिंता, और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण शिक्षा में पीछे रहना पड़ता है। इस असमानता की संरचना सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जड़ें जमाए हुए है।

सरकारी योजनाओं और नीतियों के बावजूद, जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव सीमित और असमान है। विद्यालयों में आधारभूत ढाँचागत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, और समुदाय की भागीदारी का अभाव इन असमानताओं को और अधिक गहरा करता है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल साक्षरता या प्रमाणपत्र अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है।

इस तरह, अगर भारत को सामाजिक न्याय और सतत विकास की ओर आगे बढ़ना है, तो उसे शैक्षणिक असमानताओं को प्राथमिकता के साथ समाप्त करना होगा। इसके लिए नीति, समाज और शिक्षा संस्थानों को सामिल प्रयत्न करने होंगे ताकि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या लिंग से हो, समान अवसर प्राप्त कर सके।

सुझाव

- आवरण विद्यालयों में बुनियादीढाँचे के विकास अनिवार्य रूप से कियाजाए।
- जातिगत भेदभाव के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर निगरानी समिति बने।
- लड़कियों हेतु विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षा गारंटी और बालिका प्रोत्साहन योजनाओं को सशक्त बनायाजाए।
- स्थानीय समुदाय और पंचायतों को विद्यालय प्रबंधन में भागीदार बनायाजाए।
- शिक्षकों को संवेदनशीलता एवं समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दियाजाए।
- दलित और आदिवासी बच्चों के लिए अलग शैक्षणिक परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कुमार, कृष्ण. (2023). शिक्षा और सामाजिक संरचना. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन।*
2. *यादव, सुरेश. (2022). ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था और शिक्षा. प्रयागराजः भारतीय समाजशास्त्र परिषद्।*

3. *वर्मा, सीमा. (2023). शिक्षा में सामाजिक विषमताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. कोलकाताः राष्ट्रपुस्तक भवन।*
4. *जोशी, नीलम. (2024). दलित शिक्षा की स्थिति और चुनौतियाँ. बनारसः समता प्रकाशन।*
5. *भारत सरकार. (2023). ग्रामीणशिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण. नई दिल्लीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय।*
6. *शुक्ला, अनीता. (2024). स्त्री शिक्षा और ग्रामीण भारत. जयपुरः राजस्थान विश्वविद्यालय प्रकाशन।*
7. *सिंह, अजय. (2022). जातिवाद और प्राथमिक शिक्षा में भेदभाव. पटनाः प्रगति पब्लिकेशन।*
8. *मिश्रा, अंशुमान. (2023). भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वर्गीय अंतर. भोपालः समावेश प्रकाशन।*
9. *चौधरी, अरुण. (2023). शिक्षा का सामाजिक संदर्भः ग्रामीण बनाम शहरी भारत. दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संस्थान।*
10. *भारत सरकार. (2024). समावेशी शिक्षा नीति–रिपोर्ट एवं अनुशंसा. नई दिल्लीः नीति आयोग।*
11. *शर्मा, भावना. (2023). शिक्षा में लैंगिक और जातिगत भेदभाव. लखनऊः यूनिटी पब्लिकेशन।*
12. *तिवारी, मोहित. (2022). ग्रामीण भारत में विद्यालयों की सामाजिक स्थिति. गोरखपुरः गंगानंद प्रकाशन।*
13. *नेहरू युवा केंद्र संगठन. (2023). ग्रामीणशिक्षा और युवा विकास. नई दिल्लीः युवा मंत्रालय।*
14. *भारत सरकार. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन विश्लेषण. नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय।*
15. *सेन, अनीषा. (2023). दलित और आदिवासी समुदायों में शिक्षा की पहुँच. रांचीः झारखंड सामाजिक अध्ययन केंद्र।*

❖◆❖